



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 781]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2009/वैशाख 28, 1931

No. 781]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2009/VAISAKHA 28, 1931

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मई, 2009

का.आ. 1263(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश

16 मई, 2009

श्रीमती सोनिया गांधी, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरहता के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन तारीख 7 मई, 2007 को श्री पी. राजन, संयोजक, योगम'19, कोचीन, केरल (जिसे इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) द्वारा एक याचिका राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई है;

2. और याची ने इसके पूर्ववर्ती पैरा में निर्दिष्ट अपनी याचिका में कथन किया है कि श्रीमती सोनिया गांधी, संसद् सदस्य ने 11 नवंबर, 2006 को बेल्जियम सरकार से "ग्रांड आफिसर आफ द आर्डर आफ लियोपोल्ड" की उपाधि स्वीकार करके संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन निरहता उपगत कर ली है;

3. और राष्ट्रपति ने 25 जून, 2007 को निर्वाचन आयोग को प्रथम पैरा में निर्दिष्ट याचिका में श्रीमती सोनिया गांधी, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरहता के प्रश्न पर संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन अपनी राय देने के लिए एक निर्देश किया था;

4. और निर्वाचन आयोग ने, याची द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका, पूरक दस्तावेजों, श्रीमती सोनिया गांधी, संसद् सदस्य (लोक सभा) द्वारा फाइल किए गए लिखित कथन, विदेश मंत्रालय द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों और याची द्वारा फाइल किए गए प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् अपनी राय निविदत्त की जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रथम पैरा में निर्दिष्ट याची की तारीख 7 मई, 2007 की याचिका (राय इस आदेश के साथ उपाबंध के रूप में संलग्न है) में कोई बल नहीं है और श्रीमती सोनिया गांधी, संसद् सदस्य (लोक सभा) के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन याचिका में अभिकथित निरर्हता उपगत करती है और तृतीय पैरा में वर्णित निर्देश को राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है;

5. अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करती हूँ कि श्रीमती सोनिया गांधी ने प्रस्तुत याचिका में अभिकथित आधारों पर संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं की है।

भारत की राष्ट्रपति

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

2007 का निर्देश मामला सं. 10

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

पी. राजन याची

बनाम

श्रीमती सोनिया गांधी प्रत्यर्थी

राय

श्री पी. राजन, संयोजक, 'योगम 19', कोचीन, केरल द्वारा फाइल की गई तारीख 7 मई, 2007 की याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (घ) के अधीन श्रीमती सोनिया गांधी, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी।

याची द्वारा प्रस्तुत याचिका, अनुपूरक दस्तावेजों, प्रत्यर्थी द्वारा फाइल किए गए लिखित विवरण, विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और याची द्वारा फाइल किए गए प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् आयोग ने निम्नानुसार अपनी राय प्रस्तुत की है।

राय : श्री नवीन बी. चावला, निर्वाचन आयुक्त और डा. एस.वाई. कुरैशी, निर्वाचन आयुक्त (बहुमत) के अनुसार

इस प्रभाव की राय दी गई है कि पूर्वोल्लिखित याचिका किसी गुणावगुण से विहीन है और ऊपर नामित प्रत्यर्थी के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन निरर्हता उपगत की है, जैसाकि याचिका में अभिकथन किया गया है और निर्देश को इस प्रभाव की राय के साथ राष्ट्रपति को लौटाया जाता है।

श्री एन. गोपालास्वामी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

इस प्रभाव की राय प्रस्तुत की गई है कि इस निर्देश को इस संज्ञा के साथ राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया जाए कि संविधान के अधीन यथा अनुध्यात जांच इस मामले में पूरी नहीं की जा सकी थी।

निर्वाचन आयोग की अंतिम राय

निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्तों की सेवा-शर्तें और कारबार संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 9 और धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए बहुमत द्वारा निर्वाचन आयोग की यह राय प्रस्तुत करता है कि ऊपर नामित याची की तारीख 7 मई, 2007 की याचिका किसी गुणावगुण से विहीन है और ऊपर नामित प्रत्यर्थी के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने संविधान के अनुच्छेद 102(1)(घ) के अधीन निरर्हता उपगत की है, जैसाकि याचिका में अभिकथन किया गया है। निर्देश को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग की उपरोक्त प्रभाव की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस किया जाता है।

ह./-
(एस.वाई. कुरैशी)
निर्वाचन आयुक्त

ह./-
(एन. गोपालास्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ह./-
(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 13 अप्रैल, 2009

[फा. सं. एच-11026(1)/2009-वि-II]
टी. के. विश्वनाथन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE**(Legislative Department)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th May, 2009

S.O. 1263(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

16th May, 2009

Whereas a petition dated the 7th May, 2007 under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution of India regarding alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha) has been submitted to the President by Shri P. Rajan, Convenor, Yogam'19, Cochin, Kerala (hereinafter referred to as the petitioner);

2. And whereas the petitioner has averred in his petition referred to in preceding paragraph that Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament, by accepting the title of 'Grand Officer of the Order of Leopold' from the Government of Belgium on the 11th November, 2006, incurred disqualification under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

3. As whereas the President made a reference on the 25th June, 2007 to the Election Commission seeking its opinion under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha) in the petition referred to in the first paragraph;

4. And whereas the Election Commission, after considering the petition, the supplementary documents submitted by the petitioner, the written statement filed by Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha), the documents furnished by the Ministry of External Affairs, and the rejoinder filed by the petitioner, tendered its opinion stating therein that the petition dated the 7th May, 2007 (the opinion annexed as Annexure to this order) of the petitioner referred to in first paragraph is devoid of any merit and Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha) cannot be said to have incurred disqualification under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution of India, as alleged in the petition and returned the reference referred to in third paragraph to the President;

5. Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of the article 103 of the Constitution, do hereby decide that Smt. Sonia Gandhi has not incurred any disqualification under sub-clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution, on the grounds alleged in the present petition.

PRESIDENT OF INDIA

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case No. 10 of 2007

[Reference from the President under Article 103(2) of the Constitution of India]

P. RajanPetitioner

Vs.

Smt. Sonia GandhiRespondent

OPINION

The opinion of the Election Commission was sought under Article 103(2) of the Constitution, on the question of alleged disqualification of Smt. Sonia Gandhi, Member of Parliament (Lok Sabha), under sub-clause (d) of Clause (1) of Article 102 of the Constitution of India, on the petition dated 7th May, 2007, filed by Shri P. Rajan, Convenor, 'Yogam 19', Cochin, Kerala.

1863 GT/09-2

After considering the petition, the supplementary documents submitted by the petitioner, the written statement filed by the respondent, the documents furnished by the Ministry of External Affairs, and the rejoinder filed by the petitioner, the Commission has tendered opinion as follows:

OPINION : PER Shri Navin B. Chawla, Election Commissioner and Dr. S. Y Quraishi, Election Commissioner (Majority)

Opinion has been tendered to the effect that the aforementioned petition is devoid of any merit and the respondent abovenamed cannot be said to have incurred disqualification under Article 102(1)(d) of the Constitution, as alleged in the petition, and the Reference is returned to the President with the opinion to this effect.

PER : Shri N. Gopalaswami, Chief Election Commissioner

Opinion has been tendered to the effect that the Reference may be returned to the President with the observation that the inquiry as contemplated under the Constitution could not be made in this case.

FINAL OPINION OF THE ELECTION COMMISSION

Having regard to the provisions of sections 9 and 10 of the Election Commission (Conditions of Service of Election Commissioners and

Transaction of Business) Act, 1991, the Election Commission, by majority, hereby tenders the opinion of the Election Commission that the petition dated 7th May, 2007 of the petitioner abovenamed is devoid of any merit and the respondent abovenamed cannot be said to have incurred disqualification under Article 102(1)(d) of the Constitution, as alleged in the petition. The Reference is returned to the President with the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India to the above effect.

Sd/-

(Dr. S.Y. Quraishi)
Election Commissioner

Sd/-

(N. Gopalaswami)
Chief Election Commissioner

Sd/-

(Navin B Chawla)
Election Commissioner

New Delhi

Dated : 13th April, 2009

[F. No. H-11026 (1)/2009-Leg-II]

T. K. VISHWANATHAN, Secy.